राष्ट्रीय नगरीकरण नीति
National Urbanisation Policy

नगरीकरण —

किसी भी देश के स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण हितैषी ~~में~~ स्वास्थ्य तथा सुरक्षित नगरीकरण के लिए राष्ट्रीय नगरीकरण नीति की आवश्यकता होती है।

प्रथम FYP में कृषि को प्राथमिकता देने के कारण राष्ट्रीय नगरीकरण के दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया लेकिन दूसरी FYP में उद्योग के ~~समावेश~~ विकास को ध्यान में रखते हुए नगरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। नगरीकरण की विशेष नीति निर्धारित की गई। इसी नीति के अंतर्गत 1956 में

1956 Master Plan (1) TCPO (Town and country planning organisation) गठन किया गया
कार्य TCPO का — इस संगठन ने द्वितीय FYP में देश के सभी नगरों के लिए मास्टर प्लान की योजना पर बल दिया गया। जिसकी आवादी 1 लाख या इससे अधिक हो। ~~लेकिन 3 FYP आते-आते~~

1962 Metropolitan Region Area (2) लेकिन 3 FYP आते-आते स्पष्ट हो गया कि महानगरों की आवादी तेजी से बढ़ रही है और यह नगरीय विस्फोट के प्रतीक है। अतः 3 FYP में Metropolitan region की नीति अपनाई गई। ~~इसके~~ कारण Calcutta Metropolitan ~~region~~ District का गठन किया गया।
कार्य — महानगर व इसके आस-पास के क्षेत्रों को मिलाकर समन्वित नियोजन का कार्य।

(3) City region Planning (1975) - यह नवीन नगर Region नीति का मुख्य आधार था City region का गठन। नवीन नगरीकरण नीति के दो महत्वपूर्ण विशेषता थी—

(क) नगर के विकास को उसके प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया

(ख) नगर के आंतरिक विकास, मुख्यतः गंदी बस्ती के विकास के लिए प्रयास किए गए

(4) राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग का गठन ~~नीति~~ -1985-

विशेषता / सिफारिशें

(क) नगर की आंतरिक समस्याओं को वर्णित कर गंदी बस्ती एवं आधिवासीय समस्याओं के समाधान को प्रधानता दी गई।

(ख) ऐसे प्रदेशों की पहचान जहाँ नगरीय विकास की तीव्र गति हो या तीव्र होने की संभावना हो। इस तरह 329 GEMS (Generator of Economic momentum तथा 49 SPUR's (special priority urban organisation ~~region~~ region की पहचान की गई। नगरीकरण के तीव्र वृद्धि को ध्यान रखते हुए नगरीकरण के निम्न दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए—

(क) समन्वित और पदानुक्रमिक विकास की आवश्यकता

(ख) सभी नगरों के लिए दीर्घकालीन नियोजन लक्ष्य बनाए रखना

(ग) नगरों के आर्थिक विकास के लिए गंदी बस्ती तथा आवासीय बस्ती में संरचना और सार्वजनिक सुविधाएं

(घ) भारतीय नगरों के विस्तार की आवश्यकता।

(1)

इ आयोग के रिपोर्ट के अनुरूप नगरीय विकास हेतु वर्ष त्रिपो का निर्धारण किया। जिसमें महानगरीय प्रदेश और नगर प्रदेश नियोजन का विशेष महत्व है। भारत के सभी महानगरों के लिए महानगरीय प्रदेश नि-